भारत सरकार
अंतरिक्ष विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 5

गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागदारी को प्रोत्साहित किया जाना

***5. श्री कार्तिकेय शर्मा:**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को राष्ट्र-संचालित अंतरिक्ष कार्यक्रम से वैश्विक 'अंतरिक्ष विनिर्माण केंद्र' में परिवर्तित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) एसएसएलवी के लिए निजी क्षेत्र के साथ किए गए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपग्रह (सैटेलाइट) प्रक्षेपण बाज़ार में वैश्विक हिस्सेदारी के एक महत्वपूर्ण भाग पर निजी क्षेत्र की पकड़ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (ग) इस संबंध में सभा के पटल पर विवरण प्रस्तुत है।

***

"अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की भागदारी को प्रोत्साहित किया जाना" के संबंध में गुरुवार, 29 जनवरी, 2026 को उत्तर देने हेतु श्री कार्तिकेय शर्मा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 5 के जवाब में राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत विवरण।

(क) भारत सरकार द्वारा भारत को राष्ट्र-संचालित अंतरिक्ष कार्यक्रम से एक वैश्विक 'अंतरिक्ष विनिर्माण केंद्र' में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

i. अंतरिक्ष क्षेत्र का उदारीकरण किया गया है तथा निजी क्षेत्र को आद्योपांत अंतरिक्ष गतिविधियां आयोजित करने की अनुमति प्रदान की गई है।

ii. अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी कंपनियों (एनजीई) की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, प्राधिकृत करने तथा उनकी निगरानी करने हेतु अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) की स्थापना की गई थी।

iii. एक सशक्त अंतरिक्ष परितंत्र के निर्माण हेतु विभिन्न हितधारकों द्वारा आयोजित अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियामक निश्चितता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 तैयार की गई है।

iv. भारतीय गैर-सरकारी कंपनियों को विदेशी पूंजी तक सुगमता से पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए संशोधित एफडीआई नीति जारी की है।

v. इन-स्पेस द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय विज़न एवं रणनीति की भी घोषणा की गई है, जिससे वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी।

(ख) इन-स्पेस, इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) ने मैसर्स हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत एचएएल स्वतंत्र रूप से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) का निर्माण कर सकेगी। इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के अंतर्गत, एचएएल क्रमिक रूप से एसएसएलवी के स्वतंत्र उत्पादन की दिशा में अग्रसर होगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त होगा।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखितानुसार।

****